भारत की सुरक्षा चिंताएं बनाम चीन–पाक समन्वित प्रयास

DR. VIJENDER KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT., OF POLITICAL SCIENCE
SHRI JJT UNIVERSITY, JHUNJHUNU, RAJASTHAN

सार

पाकिस्तान विदेश नीति के रुझान।तज विदेश नीति को मौलिक रूप से कार्रवाई के अजीबो गरीब फ्रेम द्वारा अन्य देशों के साथ राजनयिक व्यवहार करने की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारे इतिहास असफल समझौतों के साथ रहती है (महमूद , 2004) पाकिस्तान को अखंडता की प्रतिष्ठा का निर्माण करना है और फिर छोटे देशों के साथ विशेष रूप से रास्ते खोलने हैं। एक वोट एक वोट है, इसलिए बहुमत में छोटे देशों को एक साथ ले जाना प्रस्तावों को पारित करने में अधिक सहायता करेगा। पाकिस्तान की तकनीक तीन स्तरित होनी चाहिए। चरण 1 में, सेमिनार, सम्मेलन, और बैठकों जो सभी देशों, जहां हमारे राजनयिकों में विचार–विमर्श किया भेजे जाते हैं। उन्हें विदेश में अनिवार्य मुद्दों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जैसे कि मध्य एशियाई वस्तुओं के लिए माल ढुलाई को कम करने में बम्ब की भूमिका। जम्मू कश्मीर में छर्रों का उपयोग करके मानवाधिकारों का उल्लंघन व्यापक रूप से बढ़ा–चढ़ा कर किया जाता ळें

परिचय

यह एक बार से अधिक सत्यापित किया गया है कि चीन पाकिस्तान के पड़ोसी साथी और रणनीतिक सहयोगी को अवशेष देता है। बहरहाल, अब चीन–पाकिस्तान संबंध कई सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ, चीन न केवल पाकिस्तान के हितों को समायोजित करने के लिए एक क्षेत्रीय शक्ति है, बल्कि इसके अपने वैश्विक हित भी हैं, चीन ने अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय हितों की झलक के माध्यम से पाकिस्तान के हितों को देखा है। यह भी वास्तविकता है कि दांव कि अपने स्वयं के हित में हैं और दूसरी बात, अपने लक्ष्यों के लिए संतोषजनक संभावनाओं है पर केवल शर्त –चवूमते है । नतीजतन, चीन–पाकिस्तान चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर ऊर्जा गलियारे का निर्माण करता है और बहुत सारे अनुबंधों और डवन की औपचारिक स्वीकृति भी देता है आपसी आर्थिक, सैन्य और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए। चीन–पाकिस्तान अपने द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करते हैं और सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे।

हालांकि, चीन–पाकिस्तान सैन्य सहयोग विकसित करने के लिए चलेगा, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को झटका लग सकता है क्योंकि पाकिस्तान को द्विपक्षीय व्यापार में भारी कमी का सामना करना पड़ता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक दूसरे के मुख्य मुद्दों को निपटाने के लिए कूटनीतिक समर्थन बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, चीन–भारतीय समझ और पाकिस्तान के अतुलनीय सामरिक महत्व की सीमाओं के बावजूद, स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है।

साठ के दशक तक भारत में असुरक्षा का माहौल बना रहा। 1962 में चीन के साथ सीमा संघर्ष के साथ शुरू हुआ दशक अपने पारंपरिक सैन्य निर्माण, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत–सिंकियांग क्षेत्र में सड़कों और संचार प्रणालियों का एक परिणाम के रूप में चीनी खतरे का एक बड़ा प्रमाण देखा गया, जिसमें परमाणु क्षमता का अधिग्रहण 1964 और भारत की दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में सत्ता और स्थिति को चुनौती, इसके बाद उत्तर–पूर्वी भारत को इसका समर्थन। चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 के बाद भारत की खतरे की धारणा में जो वृद्धि हुई वह सैन्य रणनीतिक संपर्क थी।

1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता, सितंबर 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को चीनी अल्टीमेटम, युद्ध के दौरान चीन ने पाकिस्तान को जो सैन्य समर्थन दिया था और आखिरकार 1965 के बाद उसके हथियारों का पाकिस्तान में स्थानान्तरण हुआ। चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक डिजाइन भारत–ए–विज भारत को देखते हैं। दो दुश्मनों की छवि – पाकिस्तान और चीन व्यक्तिगत रूप से और देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर इस अवधि के दौरान भारतीय निर्णय निर्माताओं के दिमाग पर हावी हो गए।

भारत की सुरक्षा पर दक्षिण जल्दी सत्तर के दशक में अंतरराष्ट्रीय सामरिक क्षितिज में महत्वपूर्ण विकास में से एक चीन अमेरिकी सामान्यीकरण 1971 की गर्मियों और सामरिक धुरी के फलस्वरूप उद्भव में हेनरी किसिंजर द्वारा शुरू किया गया था। यह पूर्वी स्तर से भारत में शरणार्थियों की आमद और पाकिस्तान सरकार के जुझारू रवैये और अंततः दिसंबर 1971 में युद्ध के प्रकोप के कारण भारत के सुरक्षा माहौल के बिगड़ने के साथ आया। जिसमें 1971 की सर्दियों में चीनी और अमेरिकी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था।

समापन टिप्पणी में, यह कहा जा सकता है कि सुधार के बावजूद, चीन–भारतीय संबंध प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। दोनों, उनकी शक्ति और स्थिति जो वहां की जनता, भौगोलिक स्थिति के लिए उपयुक्त हो जाएगा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे देश '' रों आकार, और इतने पर। इसके अलावा, 21 वीं सदी में महान शक्तियों और आर्थिक दिग्गजों के रूप में दोनों राज्यों के उद्भव के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नए भू–राजनीतिक संरेखण में परिणाम हो सकते हैं। दोनों एशिया और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में अपनी

उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, दोनों राज्यों की नई आर्थिक समृद्धि और सैन्य ताकत नए तनाव पैदा करेगी क्योंकि दोनों दुनिया के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में अपने अधिकार को दर्ज करने की कोशिश करेंगे। सामरिक स्तर पर, भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं की ताकत, गुंजाइश और पहुंच का विस्तार करना जारी रखेगा। इस तरह की क्षमताओं का विकास चीनी को भारतीय इरादों से सावधान रहने का कारण प्रदान करेगा। जहां तक चीन–पाक संबंधों और चीन–भारतीय संबंधों पर इसके प्रभाव का संबंध है, यह चीन–भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण अड़चन भी रहेगा। चीन हालांकि, अब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन यह भी समर्थन नहीं करता है भारत '' रों स्थिति या तो और न ही निकट निजनतम19 में ऐसा करने की संभावना है। इसके अलावा, कई अन्य क्षेत्रों जैसे कि सीमा मुद्दे, अरुणाचल प्रदेश, ऊर्जा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, आदि में, दोनों अलग–अलग विचार रखेंगे और अपने–अपने स्टैंड पर टिके रहेंगे।

चीन–अमेरिकी रणनीतिक चुनौती के लिए भारत की प्रतिक्रिया पूर्व सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के रूप में आई। भारतीय निर्णय निर्माताओं ने चीन–पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक साथ आने से देश की सुरक्षा के लिए जटिल चुनौतियों के लिए एक इष्टतम प्रतिक्रिया महसूस की, न केवल पर्याप्त रक्षा तैयारियों की आवश्यकता थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण एक बाहरी शक्ति के साथ रणनीतिक संबंध बनाने के लिए अनुकूल था भारत। सोवियत संघ, जो चीन–अमेरिकी रणनीतिक समझ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था, आदर्श विकल्प बन गया – परिणाम 1971 अगस्त की भारत–सोवियत मित्रता संधि के रूप में प्रसिद्ध था। इस संधि ने न केवल चीन–अमेरिकी और चीन के लिए एक प्रतिकार शक्ति का गठन किया। दिसंबर 1971 के युद्ध में चीनी या अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक निरोध के रूप में कार्य करके, गैर–संरेखण पर समझौता किए बिना, पाक रणनीतिक सहयोग लेकिन भारत के सुरक्षा हितों की भी सेवा की।

उप–महाद्वीप में अपनी प्रमुख स्थिति की स्थापना के बाद 1971 के बाद भारतीय सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआय पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता, परमाणु स्थिति की प्राप्ति, मई 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के परिणामस्वरूप, कश्मीर समझौते का शेख अब्दुल्ला के साथ, भारतीय संघ के साथ सिक्किम का एकीकरण और अंत में चीन के साथ राजदूत संबंध। शायद भारत के नीति निर्माताओं के लिए चिंता का एकमात्र स्रोत 1971 के बाद की अवधि में पाकिस्तान द्वारा पुनः आयुध कार्यक्रम का सख्ती से पीछा करना था, जो परमाणु क्षमता की अपनी खोज के साथ मिलकर था जो अब उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार सत्तर के दशक के शुरुआती भाग में ही शुरू हुआ था।

पाकिस्तान को विश्वास था कि भारत से पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर हमला करने में चीनी मदद निर्णायक और आगामी होगी। चीन और पाकिस्तान से सन्निहित स्तर पर खतरों ने भारत में नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। चीन बड़े पैमाने पर अपनी बढ़ती रक्षा ताकत, तिब्बत में मिसाइलों को रखने, सड़कों के नेटवर्क के निर्माण और सिंकियांग क्षेत्र में संचार के कारण सैन्य रणनीतिक खतरे का स्रोत बन गया।

हिंद महासागर में पश्चिमी उपस्थिति पर भारत की कोमलता काफी हद तक भारत की सुरक्षा और राजनीतिक विचारों से प्रचलित है। बहुपक्षीय सुरक्षा गारंटी की तलाश बाद में भारत की नरम और कम मुखर भारतीय महासागर कूटनीति की जड़ में दिखाई देती है। उस समय नेहरू शायद यह मानते थे कि चीन से भारत पर संभावित भविष्य के हमलों के खिलाफ अमेरिकी सातवें बेड़े की मौजूदगी में बाधा होगी। जैसा कि भारत अपनी सुरक्षा पर दो मोर्चे की आशंका जता रहा था। भारत के लिए दो मोर्चे के खतरे की संभावना की शुरुआत 1990 के दशक में कश्मीर में तनाव में हुई थी। भारत को कश्मीर में पुनर्वितरण के लिए चीन की भारतीय सीमा से नौ सैन्य टुकड़ियों को वापस खींचने के लिए मजबूर किया गया है।

प्रोजेक्टिंग इंडिया हेग्मोनिस्ट :–

चीन और पाकिस्तान दोनों दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र में छोटे राज्यों पर मालिक होने के इरादे के साथ भारत को एक हेगड़ेवादी राज्य के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इस रुख के दो निहितार्थ हैं। एक आसन्न छोटे राज्यों के बीच एक भय मनोविकार पैदा करना है, और अन्य क्षेत्र में एकध्रुवीय शक्ति की हस्तक्षेप और यहां तक कि उपस्थिति को वैध बनाना है।

भारत के उत्तर पूर्व में पाकिस्तान और चीन की भागीदारी, बांग्लादेश में विद्रोही समूहों के लिए अभयारण्य आदि भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं। ऑल आउट युद्ध की उच्च आर्थिक और कूटनीतिक लागत के कारण, पाकिस्तान जिस तरह से भारत को लगातार खून बहाने के उद्देश्य से भारत के साथ युद्ध कर रहा है, उसके युद्ध का एक निम्न ध गुप्त स्तर निचले स्तर पर है, जो भारत के लिए हानिकारक बलों के लिए एक आसान विकल्प है। इस तरह के निम्न स्तर के संघर्षों की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ने भारत के छोटे पड़ोसियों को इसके खिलाफ जुटाने में निहित स्वार्थ हैं। अगर जम्मू–कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में छद्म युद्ध को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तान, चीन और म्यांमार के साथ तालमेल होता है तो भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

पाकिस्तान और चीन ने कभी भी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में सड़कों पर जाकर भारत के पड़ोसियों और उनकी नीतियों में हेरफेर करने की कोशिश की है। इसके द्वारा वे भारत की बढ़ती शक्ति को रोककर रखना चाहते हैं। भारतीय विद्रोहियों के लिए पाकिस्तानी समर्थन का परिणाम अर्थव्यवस्था, रक्षा आदि की प्रकृति में भारत के लिए उच्च बोझ है। इस सबने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक रणनीतिक विद्वता को जन्म दिया है जो स्वाभाविक रूप से भारतीय हितों के लिए अक्षम है।

असममित भारत और चीन की शक्ति राजनीति का संतुलन :–

भारत चीन के संबंध में गहराई से आशंकित है। दूसरी ओर चीनी, भारत से एक गंभीर खतरे का अनुभव नहीं करते हैं, और यह समझना मुश्किल है कि भारतीय चीन और इसकी गंभीर शिकायत क्यों पा सकते हैं।

चीन के भारतीय डर का प्रमुख आधार चीन पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी है। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत मानता है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद हुई कई घटनाओं से चीन–पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी का उद्‌भव बरकरार रहा। पाकिस्तान के साथ चीन के रक्षा सहयोग, पाकिस्तान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम में उसकी सहायता और पाकिस्तान द्वारा मिसाइलों और परिष्कृत हथियार प्रणाली की बिक्री के बारे में भारत की चिंता, चीनी पक्ष को बताई गई। चीन ने अपनी परमाणु शस्त्रागार और मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने में हाल के वर्षों में जो प्रगति की है, उसका भारतीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा।

भारत–पाकिस्तान सीमा के साथ–साथ पाकिस्तान की लॉजिस्टिक क्षमताओं का उन्नयन, पाकिस्तान की वायु संचालन क्षमताओं को मजबूत करना और नौसेना को पता चलता है कि चीन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के पक्ष में जो संतुलन है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। 1997–98 भारतीय रक्षा रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन की सहायता सीधे भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। पाकिस्तान को सैन्य रूप से मजबूत बनाकर, चीन पाकिस्तान को भारतीय प्रभुत्व से मुक्त रखने की कोशिश करता है और भारत को लगातार चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त है। चीन–पाकिस्तान प्रवेश द्वार की गहराई और स्थायित्व भारतीय रक्षा योजनाकारों को इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि चीन या पाकिस्तान भारत और दूसरे के बीच किसी भी बड़े पैमाने पर संघर्ष में प्रवेश करेंगे। ऐसा करके बीजिंग ने भारत को अपने सैन्य बलों को विभाजित करने के लिए मजबूर किया है। प्रभावी रूप से, चीन–पाकिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण भारत के सामने दो खतरे हैं।

उपरोक्त विश्लेषण बताता है कि बिना किसी संदेह के चीन पाकिस्तान पर एक परम सुरक्षा कंबल के रूप में खेलता है, लेकिन अगर कोई 1965 और 1971 के भारत–पाक युद्धों को देखता है तो पाकिस्तान को अपमानजनक पराजयों से बचाने में चीन की भूमिका में कमियां पाता है। यह कहा जाता है कि चीन के इरादे आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं और वे पाकिस्तान को मजबूत करके भारत को 'संतुलित' करने की इच्छा से परे हैं। चीन ने ''भारत को संतुलित करने'' के उद्देश्य से पाकिस्तान को परमाणु ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की हो सकती हैय लेकिन यह संभावना है कि चीन की गणना कहीं अधिक जटिल थी और रणनीतिक रूप से भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ी। नुक्सेस और मिसाइल उपकरण को इस्लामाबाद में स्थानांतरित करके। बीजिंग ने कुशलतापूर्वक भारत–चीन परमाणु बहस को भारत पाकिस्तान प्रतियोगिता में बदल दिया है ताकि एनपीटी और सीटीबीटी में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान पर विश्व निकाय दबाव डाला जा सके।

परमाणु खतरा पर्यावरण :–

चीन–पाकिस्तानी सैन्य संबंध, विशेष रूप से इसके परमाणु घटक, का भारतीय सुरक्षा और नीतियों पर प्रभाव पड़ा है। भारत के लिए चीनी परमाणु और मिसाइल पाकिस्तान में स्थानांतरित हो जाता है, जो बीजिंग द्वारा एनपीटी पर आरोप लगाए जाने के बाद भी जारी रहता है और मिसाइल ट्रांसफर कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देता है, यह दर्शाता है कि एक परमाणु हथियार राज्य अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर सकता है और इसके साथ भाग सकता है। अमेरिका के हिस्से पर कुछ सामयिक विरोधों को छोड़कर, एनपीटी के चीनी उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा और बड़े चुप रहे हैं। विडंबना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर एनपीटी का पालन करने और अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का दबाव बना रहा है। भारतीय अभिजात वर्ग ने चीन के साथ चीन के परमाणु ६ मिसाइल संबंध को क्षेत्रीय और वैश्विक क्रम में भारत को नेतृत्व की भूमिका से वंचित करने के लिए डिजाइन की गई एक जानबूझकर भागीदारी की रणनीति के रूप में देखा है। साठ के दशक की शुरुआत से चीन का पाकिस्तान में रणनीतिक निवेश है और वह पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। पाकिस्तान को चीन द्वारा खतरा नहीं माना जा रहा है, जबकि भारत बीजिंग के अनुमान और भारत की प्रेरणा से विश्वसनीय है।

पाकिस्तान ने अपने नए प्रदर्शन वाले परमाणु कवच के पीछे सुरक्षित महसूस किया, और 1999 के शुरू में, जब उसने भारतीय कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में अपनी घुसपैठ शुरू की, एक संभावित परमाणु युद्ध

के दर्शक को बढ़ाकर लंबे समय से कश्मीर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करने की मांग की। कारगिल युद्ध ने इसे दोनों ओर से परमाणु खतरों के साथ लाया। एक अध्ययन के अनुसार, दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय नेताओं ने कारगिल युद्ध के दौरान कम से कम एक दर्जन परमाणु खतरों का आदान–प्रदान किया। पाकिस्तान के आधिकारिक इंटरनेट पेज ने चेतावनी दी कि कश्मीर एक ''परमाणु फ्लैश बिंदु'' था। जबकि कारगिल–द्रास सेक्टर में भारत के सैन्य लाभ लेने का पाकिस्तान का निर्णय पूरी तरह से दोनों देशों के नाभिकीयकरण का परिणाम नहीं था, दोनों देशों के बीच खेलने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक की पाकिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका थी उस संघर्ष को शुरू करने का निर्णय, विशेष रूप से एक बार अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व बदल गया।

कारगिल युद्ध ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के अधिग्रहण के साथ पाकिस्तान सीमित युद्ध में भारत को उलझाने के अतीत की तुलना में अधिक आश्वस्त था। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान ने अपनी परमाणु हथियारों की क्षमता को भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता के खिलाफ 'इक्विलाइजर' के रूप में देखा। यह कारगिल के अनुभव के बाद था, जिसमें भारत में पुरुषों और सामग्री की भारी लागत थी, भारतीय रक्षा नियोजक एक 'सीमित युद्ध' से लड़ने की संभावना के लिए तैयारी करते दिखते हैं। "सीमित युद्ध की अवधारणा को 1999 में नई दिल्ली में एक सेमिनार में रखा गया था, जिसमें तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक का एक पेपर भी शामिल था।

पारंपरिक ''संतुलन–असंतुलन'' के निधन ने पाकिस्तान को अपनी पारंपरिक हीनता की भरपाई के लिए परमाणु निरोध पर अधिक निर्भरता का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तानी रक्षा योजनाकारों का मानना है कि उनके परमाणु परीक्षणों ने पारंपरिक हथियारों में भारतीय श्रेष्ठता को समतल कर दिया है और यह स्थिति केवल तभी बनी रह सकती है जब पाकिस्तान पूर्व–परमाणु परमाणु हमले शुरू करने के विकल्प को बरकरार रखे। पारंपरिक श्रेष्ठता का मुकाबला करने के साधन के रूप में परमाणु निरोध के इस्लामाबाद गोद लेने से भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्निहित अस्थिर परमाणु निरोध के उभरने में भी योगदान है। दुर्भाग्य से, भारत और पाकिस्तान के परमाणु रुख का स्पष्टीकरण, उनके मिसाइल वितरण प्रणाली के चल रहे संवर्द्धन के साथ, यह मानकर चल रहा है कि परमाणु हथियारों ने उप–महाद्वीप में क्या स्थिरता लाई है।

रक्षा दुविधा :–

भारतीय रक्षा और सुरक्षा नीतियां चीनी और पाकिस्तानी खतरों और सैन्य और राजनयिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की कोशिश करती हैं। भारत की पाकिस्तान पर सैन्य श्रेष्ठता है और वह अपने दम पर युद्ध जीतने में सक्षम है। लेकिन चीन के खिलाफ भारत की सफलता कूटनीतिक और

सैन्य दोनों मोर्चों पर खतरा है। 20 वीं शताब्दी के धुंधलके में, पिछले कई वर्षों में भारतीय रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है। 1997 में बजट में बड़ा उछाल आया, लगभग 24.4 प्रतिशत। अगली बड़ी छलांग 2000–01 में थी जब इसे 28.2 प्रतिशत बढ़ाकर + 13.62 बिलियन कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2001–02 के लिए इसमें लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले साल, 2002–03 में, इसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रक्षा बजट भारत के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के आंशिक रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए भारत में कई नए अधिग्रहण हुए हैं।

पोखरण में चीन–पाक कारक :–

यह सर्वविदित है कि पोखरण ने पहली बार भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को चित्र में लाया था। परीक्षण का निर्णय राजनीतिक था, क्योंकि परीक्षण शांतिपूर्ण प्रकृति का था। यह भारतीय सेना का निर्णय नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना परमाणु निरोध के साथ लगी। यह पाकिस्तान में परमाणु विकास (1970 के दशक), चीन–पाकिस्तान सैन्य संबंधों के उद्भव, और अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी परमाणु हथियार गतिविधि की सहनशीलता के संदर्भ में हुआ।

भारतीय सैन्य तंत्र के आधुनिकीकरण के बाद भारतीय सेना ने परमाणु सवालों में चिंता और रुचि दिखाई और भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक पारंपरिक युद्ध छेड़ने की अपनी क्षमता के बारे में सुरक्षित महसूस किया, और चीन और पाकिस्तान के परमाणु विकास और भारतीय के लिए उनके निहितार्थ के बाद। सुरक्षा ने भारतीय पेशेवर और सार्वजनिक राय में एक नमकीन का विकास किया। के रू–बरू पाकिस्तान और चीन के तेजी से बिगड़ अस्सी के दशक तक, नई दिल्ली अपने रिश्तेदार की स्थिति को देखा। संयुक्त राज्य जो भारत के दोनों प्रतिद्वंद्वियों के करीब चले गए थे, एक अतिरिक्त खतरा दिखाई दिया।

निष्कर्ष

भारत की सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे पाकिस्तान और चीन और उनके बीच रणनीतिक संबंधों पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग को रेखांकित करने वाले कारक आपसी हित हैं। दोनों का उद्देश्य क्षेत्र में भारतीय प्रभाव के विस्तार को शामिल करना था और किसी भी खतरे का मुकाबला करना था जो भारत या तो चीन या पाकिस्तान के लिए कर सकता है।

भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते के समापन के तुरंत बाद भारत–चीन संबंधों के सुरक्षा आयाम का विकास हुआ। चीन ने पाकिस्तान की सीटो की सदस्यता के साथ जो समझ दिखाई वह स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ थी। क्योंकि इसके द्वारा चीन ने पाकिस्तान को भारत के दरवाजे पर शीत युद्ध की राजनीति लाने के लिए एक तरह से समर्थन किया। ''दस सिद्धांतों'' में एक खंड को सम्मिलित करने के लिए चीन की सहायता और सहयोग जो कि पाक आक्रमणों को आत्मरक्षा के लिए सैन्य संधि में शामिल होने के अधिकार के लिए बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया था चीन न केवल विशेष रूप से भारत के खिलाफ साजिश आक्रामकता के आरोप में पाकिस्तान को पछाड़ दिया है, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति को भारी झटका दिया। यह भारत का सीधा संबंध था जो अपनी विदेश नीति का बचाव करने के लिए साहसपूर्वक लड़ रहा था। एक तरह से भारत को एक आक्रामक देश के रूप में ब्रांडेड करने के मामले में चीन का पाकिस्तान को समर्थन। भारत के खिलाफ दबाव के उपकरणों के रूप में पाकिस्तान की सैन्य संधि का उपयोग किया गया था।

भविष्य की संभावनाएं

इसलिए, पाकिस्तान के प्रति चीन का रवैया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों द्वारा निर्धारित है। इसी तरह, पाकिस्तान का चीन नीति चीन–भारतीय और भारत–अमेरिकी संबंधों की स्थिति से तय होती है। साठ के दशक में चीन–पाकिस्तानी संबंधों में बढ़ती अंतरंगता हो सकती है चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव और बढ़ते जा रहे हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग। यदि हम आधार स्वीकार करते हैं, जैसा कि यह लेख करता है, कि पाकिस्तान की विदेश नीति इसके द्वारा निर्धारित होती है भारत, पाकिस्तान के साथ अपने शक्ति संबंधों के साथ निरंतर व्यस्तता चीन की नीति इस पाकिस्तानी उपद्रव का एक बहुत तार्किक परिणाम है। चीन के प्रति पाकिस्तान की नीति को ही समझा जा सकता है। भारत–पाकिस्तान और चीन–भारतीय संबंधों का संदर्भ। इसकी निर्भरता चीन के बीच बेहतर संबंधों की स्थिति में ही इसे कम किया जा सकता है उपमहाद्वीप पर दो बहनें देश।

संदर्भ

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज संख्या 1।

क्यू एंड ए चीन–पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौते पर चोंग क्वान द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता श, 27 नवंबर, 2006, सं। 18. फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृ– 54।

सैयद फजल–ए–हैदर, पदह पाकिस्तान में चीन का बढ़ता कदम ', एशिया टाइम्स ऑनलाइन, 30 नवंबर, 2006, इशरत हुसैन, सं। 19, पृ– 7।

महमूद–उल–हसन खान, पहीजे पाक–चीन संबंधों की नई ऊंचाई श, 5 मार्च, 2006 को फजल–उर–रहमान में उद्धृत किया गया, संख्या 3, पृष्ठ 58।

मुक्त व्यापार समझौते पर चीनी व्यवहार्यता अध्ययन, फजल–उर–रहमान में उद्धृत, संख्या 3, पृष्ठ 64।

मांगी, प पाकिस्तान नेशनल बैंक सीकिंग चाइना वेंचर पार्टनर ', इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, 18 अप्रैल, 2007, चीन पर संक्षिप्त, निवेश बोर्ड, पाकिस्तान सरकार, सं– 25

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज श, संख्या 1. फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृष्ठ 66।

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज श, संख्या 1।

पाकिस्तान चीनी निवेश का स्वागत करता हैरू पी एम, पाकिस्तान का एसोसिएटेड प्रेस, सैयद फजल–ए–हैदर, 'चीनी आई पाकिस्तान का रियल एस्टेट', एशिया टाइम्स ऑनलाइन, 17 जनवरी, 2007,।

समाचार, 22 फरवरी, 2006, फजल–उर–रहमान में उद्धृत किया गया, संख्या 3, पृष्ठ 67।

फजल–उर–रहमान, संख्या 3, पृष्ठ 59।

जॉन डब्ल्यू गवर, सेंट्रल, साउथ–वेस्ट और साउथ एशिया के साथ चीन के ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक का विकास ', द चाइना क्वार्टरली, 185, मार्च 2006, पृष्ठ 1–2।

साईबाल दासगुप्ता, पाक बेंड ओवर ओवर बीजिंग, ऑफर ऑयल बैकअप ', द टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 मार्च, 2007।

मुहम्मद इफ्तिखार राजा, काराकोरम हाइवे–द फ्रेंडशिप ब्रिज अक्रॉस द हिमालय ', बीजिंग रिव्यू, 8 जून, 2006, पृष्ठ 7।

डॉन, 5 जुलाई 2006, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स पाकिस्तान, 34 (156), 6 जुलाई 2006, पृष्ठ 2 में उद्धृत किया गया।

ग्वादर में निवेश करने के लिए चीन इतना उत्सुक क्यों है? 'पाकिस्तान और खाड़ी अर्थशास्त्री, 29 मई – 4 जून, 2006, पृष्ठ 56।

डॉन, 20 फरवरी, 2007, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स पाकिस्तान, 35 (43), 21 फरवरी, 2007, पृष्ठ 40 में उद्धृत किया गया।

डेविड मोंटेरो,, चीन, पाकिस्तान टीम एनर्जी अप ', द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, 13 अप्रैल, 2007,

21 फरवरी 2006 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संयुक्त बयान का पाठ

पाकिस्तान–चीन एनर्जी फोरम हेल्ड इन इस्लामाबाद श, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मामलों का मंत्रालय, 3 मई, 2006, 25 नवंबर, 2006 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच संयुक्त वक्तव्य निरुपमा सुब्रमण्यन,, चीन, पाकिस्तान इंक मुक्त व्यापार समझौता द हिंदू, 25 नवंबर, 2006।

पाकिस्तान, चीन को आगे डीप स्ट्रेटेजिक टाईज, संख्या 1।

राजदूत (सेवानिवृत्त) इशरत अजीज, ंदक गल्फ ऑयल एंड इंडियाज एनर्जी नीड्स ', भारत स्ट्रेटेजिक, 1 फरवरी, 2006, पृष्ठ 47–48।

नंदकुमार जे, भारत, चीन और ऊर्जा सुरक्षा एशिया टाइम्स, 7 फरवरी, 2004

स्टीव ए यतिव और चुनलॉन्ग लू, ल्मज चाइना, ग्लोबल एनर्जी एंड द मिडल ईस्ट श, मिडिल ईस्ट जर्नल, 61 (2), 2007, पृष्ठ 199।

शमीम अहमद रिजवी, ंद क्या पाकिस्तान एक ऊर्जा संपन्न देश है? , पाकिस्तान और गल्फ इकोनॉमिस्ट, जुलाई 3–9, 2006, , पृष्ठ 19।